भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 861
उत्तर देने की तारीख 26 जून, 2019

4जी स्पीड

861. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत 4जी स्पीड के मामले में पाकिस्तान, अल्जीरिया और अन्य छोटे और गरीब देशों से भी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार कंपनियां वित्तीय बोझ का सामना कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन कंपनियों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ 4जी स्पीड धीमी होने के लिए उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ड़) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श करके इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. ने अभी तक भी 4जी कनेक्शन देने शुरू नहीं किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क)-(ख): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विश्लेषणपरक पोर्टल के आधार पर दिनांक 01.12.2018 से 31.05.2019 की अवधि के लिए देश में प्रचालक-वार औसत डाउनलोड 4जी स्पीड नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

प्रचालक	औसत डाउनलोड 4जी स्पीड (एमबीपीएस में)
रिलायंस जियो	20.8
एयरटेल	9.6
वोडाफोन	6.7
आइडिया	6.3

उपर्युक्त ट्राई परिणाम पिछले छः माह के दौरान प्रयोक्ताओं द्वारा शुरू की गई गति जांच के दौरान 'क्राउड-सोर्सिंग' आधार पर एकत्रित किए गए डाटा गति के नमूनों और ट्राई माई स्पीड ऍप द्वारा शुरू की गई बैक ग्रांउड जांच पर आधारित हैं।

सरकार के पास अन्य देशों में औसत 4जी स्पीड संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग)-(ड़): दिनांक 29.03.2017 को आयोजित भारत सरकार के सचिवों की समिति में दूरसंचार सहित अनेक क्षेत्रों में दबावग्रस्त बैलेंस शीट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी । आरबीआई के सर्कुलर द्वारा दबावग्रस्त वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए बैंकों को निदेश भी दिए गए थे। परिणामस्वरूप, निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ दिनांक 16.05.2017 को एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया था:

(i) दूरसंचार क्षेत्र में व्यवहार्य एवं भुगतान क्षमता को प्रभावित करने वाले व्यवस्थित मुद्दों की जांच करना और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना।

(ii) दूरसंचार क्षेत्र के लिए नीतिगत सुधार और कार्यनीतिपरक पहलें।

अंतर-मंत्रालयी समूह ने दिनांक 31.08.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार उद्योग का कुल ऋण 7.88 लाख करोड़ रूपए का था।

दूरसंचार प्रचालकों की बकाया ऋण देयताएं

(रु0 करोड़ में)

विवरण	**दूरसंचार सेवा प्रदाता**	**टॉवर कंपनियां**	**कुल**
भारतीय ऋण	159675	18049	177724
विदेशी ऋण	83918		83918
कुल बैंक/विदेशी निवेश ऋण	**243593**	**18049**	**261642**
बैंक गारंटी	50000		50000
दूरसंचार विभाग की आस्थगित स्पेक्ट्रम देयताएं	295864		295864
अन्य त्रिपक्षीय देयताएं	175464	4763	180227
कुल बाह्य देयताएं	**764922**	**22812**	**787734**

आईएमजी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रमुख सिफारिशें की हैं:-

(i) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उस वक्त अनुमेय 10 किस्त के बजाय अधिक किस्तों (16) के विकल्प के लिए एक बार अवसर दिया जाए।

(ii) दूरसंचार विभाग यह उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी करे कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना के प्रयोजनार्थ स्पेक्ट्रम के कारोबार से प्राप्त लाभ ही राजस्व का भाग होगा।

(iii) पीएलआर के स्थान पर आरबीआई द्वारा लागू की गई तारीख अर्थात 01 अप्रैल 2016 से एसबीआई की एक वर्षीय एमसीएलआर लागू की जाए।

आईएमजी रिपोर्ट पर दूरसंचार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

(i) दूरसंचार सेवा प्रदाओं (टीएसपी) को वर्तमान में अनुमेय 10 किस्तों के बजाय अधिक किस्तों (अधिकतम 16 किस्तों) के विकल्प का एक बारगी अवसर दिया गया।

(ii) एसबीआई की एक-वर्षीय एमसीएलआर को पीएलआर के बजाय एसबीआई द्वारा लागू की गई तारीख अर्थात 01 अप्रैल 2016 से लागू किया गया है।

ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 4जी स्पीड का दूरसंचार द्वारा झेले जा रहे वित्तीय संकट से कोई संबंध है।

(च): बीएसएनएल ने 2100 मेगाहर्ट्स बैंड के वर्तमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए अपने लाइसेंसी सेवा क्षेत्रों में 4जी सेवाएं पहले से ही शुरू कर दी हैं और अब तक 5921 4जी बीटीएस शुरू हो चुके हैं। एमटीएनएल को अपने दोनों एलएसए में 4जी सेवाएं अभी शुरू करनी हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी सहायता के साथ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की स्वीकृति के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार योजना में उपर्युक्त अनुरोध को शामिल किया गया है।

******